Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में MSME की भूमिका

स्वप्निल चौहान*

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को आर्थिक विकास और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक गतिमान इंजन के रुप में स्वीकृत किया गया है। यह क्षेत्र पिछले पाँच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, MSME न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पूँजी लागत पर के रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होते है अपितु ग्रामीण क्षेत्रो में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। एमएसएमई समयक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगो के पूरक बने है और यह क्षेत्र देश के सामाजिक- आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। भारत में उद्योगों को मुख्यत: दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

1. विनिर्माण उद्यम
2. सेवा उद्यम (जो सेवाएँ प्रदान करने में लगे हुए है)

उद्यम को दोनो श्रेणियों को संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण उद्योगो के लिए) में उनके निवेश या सेवाएँ प्रदान करने या प्रदान करने वाले उद्यमो के उपकरणों के मामले में उनके निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी में वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमो के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले निवेश की वर्तमान सीमा इस प्रकार है –

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम	सेवा उद्यम
सूक्ष्म	25 लाख रु तक	10 लाख रु तक
लघु	25 लाख रु से 5 करोड़ रु	10 लाख रु से 2 करोड़ रु तक तक
मध्यम	5 करोड़ रु से10 करोड़ रु तक	2 करोड़ रु से 5 करोड़ रु तक

वर्तमान नीति एवं ढांचा – लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MISMED), 2006 इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बनाने का प्रयास करता है। यह उद्यम की अवधारणा की मान्यता के लिए पहली कानूनी रुपरेखा प्रदान करता है। जिनसे विनिर्माण और सेवा दोनो संस्थाएँ शामिल है। यह प्रथम बार मध्यम उद्योगो को परिभाषित करता है, और न उद्यमों के तीन स्तरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगो को एकत्रित करने का प्रयास करता है। अधिनियम हितधारको के सभी वर्गों, विशेष रूप से उद्यमो की तीन वर्गो के संतुलित प्रतिनिधित्व और सलाहार कार्यो की एक विस्तृत शृखंला के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक परामर्श तंत्र भी प्रदान करता है।

परिक्षण प्रयोगशालाएँ – वर्तमान में देश में कई परिक्षण प्रयोगशालाएँ हैं जो सूक्ष्म इकाइयों सहित सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करती है कुछ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादो, विशेष रूप से चमड़े के वस्तुओं के लिए विशेष परीक्षण सुविधाएं देश में उप्लब्ध नहीं है। निर्यात करने वाली MSME इकाइयों विदेशी परीक्षण प्रयोगशालाओं से इस सुविधाओं का लाभ उठा रही है। ऐसे में, देश में अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता है। यह अनुशंसा की गई कि कम से कम 100 संख्याये MSME के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता वाली परिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाए। यह गतिविधि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत की जा सकती है। मंत्रालय के अन्तर्गत मौजूदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन की भी आवश्यकता है।

रोजगार के अवसर – भारत में एमएसएमई क्षेत्र ने भारतीय आबादी के लिए रोजगार के सबसे बड़े अवसरो को पैदा किया है, इसके बाद कृषि क्षेत्र में यह अनुमान लगाया गया है। एमएसएमई न केवल बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपितु लघु उद्योग क्षेत्र में अचल संपत्तियों में एक लाख रुपये का निवेश रोजगार पैदा करता है ।बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से निम्न पूंजी लागत पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद मिलती है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है, राष्ट्रीय आय और धन का अधिक न्यायसंगत वितरण होता है। यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भारी योगदान देता है। यह क्षेत्र मूल्य के संदर्भ में देश के विनिर्माण उत्पादन, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्र विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत और देश के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत योगदान देता है, जिससे पूरे देश में 26 मिलियन से अधिक इकाइयों में लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। पारंपरिक से लेकर उच्च तकनीक वाली वस्तुओं तक 6000 से अधिक उत्पाद हैं, जिनका निर्माण भारत में 35 एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि एमएसएमई क्षेत्र स्वरोजगार और मजदूरी-रोजगार दोनों के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है, कृषि क्षेत्र के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास की उच्च दर में योगदान देता है, बल्कि कम लागत पर गैर-कृषि आजीविका के निर्माण, सशक्त क्षेत्रीय विकास, सामाजिक संतुलन, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास और इन सबसे ऊपर, असंख्य तरीकों से एक समावेशी और मौद्रिक समाज के निर्माण में भी योगदान देता है।

निर्यात प्रोत्साहन – MSME क्षेत्र से निर्यात प्रोत्साहन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। MSME को अपने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए

निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

1. MSME निर्यातको के उत्पादो को अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाता है और किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कि जाती है।
2. MSME निर्यातको को नवीनतम पैकेजिंग, मानको एवं तकनीकी से परिचित करना। भारतीय पैकेजिंग सस्थान के सहयोग से देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यातको के लिए पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते है।
3. MSME विपणन विकास सहायता योजना के तहत, व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में व्यक्तियों को विदेशी मेली प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

बुनियादी ढांचे का विकास – औद्योगिक संपदा की स्थापना और एमएसएमई के लिए बिजली वितरण नेटवर्क, दूरसंचार, जल निकासी और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़कें, बैंक, कच्चे माल, भंडारण और तकनीकी बैंक अप सेवाएं आदि और विपणन सुविधाएं, सामान्य सेवा सुविधाएं आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए (आईआईडी) योजना 1994 में शुरू की गई थीं। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत ढांचागत विकास को कवर करती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और 50 प्रतिशत औद्योगिक भूखंड सूक्ष्म उद्यमों के लिए आरक्षित हैं।

मौजूदा औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन/ मजबूतीकरण का प्रावधान है। आईआईडी केंद्र स्थापित करने की अनुमानित लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) 5 करोड़ रुपये (51.25 मिलियन) है। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों के मामले में 40 प्रतिशत और उत्तर पूर्व क्षेत्र (सिक्किम सहित) के लिए 80% तक प्रदान करती है। आईआईडी योजना की सभी विशेषताओं को बरकरार रखा गया है। और इसे श्नए क्लस्टर और एमएसईसीडीपी के रूप में कवर किया गया ।

अवसर – निम्नलिखित कारकों के कारण एमएसएमई में अवसर बहुत अधिक हैं।

1. कम पूंजी लागत
2. लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए सरकारी आरक्षण द्वारा व्यापक प्रचार और समर्थन
3. प्रोजेक्ट प्रोफाइल
4. वित्त पोषण और सब्सिडी मशीनरी खरीद
5. कच्चे माल की खरीद
6. जनशक्ति प्रशिक्षण
7. तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल
8. टूलींग एवं परीक्षण सहायता
9. सरकार द्वारा विशेष खरीद के लिए आरक्षण
10. निर्यात प्रोत्साहन
11. उत्पादों के लिए निर्यात क्षमता में वृद्धि
12. बड़े पैमाने के क्षेत्र में आने वाली ग्रीन फील्ड इकाइयों की संख्या में वृद्धि के कारण सहायक इकाइयों की समग्र आर्थिक विकास के कारण घरेलू बाजार के आकार में मांग में वृद्धि बड़े पैमाने के क्षेत्र एवं लघु उद्योग क्षेत्र ने विगत कई वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे देश को व्यापक औद्योगिक विकास और विविधीकरण हासिल करने में सक्षम बनाया है।

अपनी कम पूंजी सघनता और उच्च श्रम अवशोषण प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र ने रोजगार सृजन और ग्रामीण औद्योगीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है स यह क्षेत्र प्रौद्योगिकियों, पूंजी, और नवीन विपणन प्रथाओं के माध्यम से पारंपरिक कौशल और ज्ञान की ताकत का निर्माण करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। लघु उद्योग क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने का यह उपयुक्त समय है। यह अपेक्षाकृत भारतीय उद्योग की एक अनिवार्य विशेषता और मांग संरचना पर आधारित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह विशेषता विभिन्न प्रकार की इकाइयों के लिए पूरक अस्तित्व की अनुमति देती है। हालांकि, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कारण पूंजी, प्रौद्योगिकी और विपणन में कमी रही है। इसलिए, सरकारी समर्थन के साथ उदारीकरण की प्रक्रिया इस क्षेत्र में इन चीजों के प्रसार को आकर्षित करेगी। लघु उद्योग क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे देश को व्यापक पैमाने पर औद्योगिक विकास विविधीकरण हासिल करने में सक्षम बनाया अपनी कम पूंजी सघनता और उच्च श्रम अवशोषण प्रकृति के कारण एमएसएमई क्षेत्र ने रोजगार सृजन और ग्रामीण औद्योगीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र प्रौद्योगिकियों, पूंजी और नवोन्मेषी विपणन पद्धतियों के माध्यम से हमारे पारंपरिक कौशल और ज्ञान की ताकत का निर्माण करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है।

निष्कर्ष – निष्कर्षत:, भारत का एमएसएमई क्षेत्र प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद श्रृंखला के बल पर आज वैश्विक विकास के प्रवेश द्वार पर है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार में प्रवेश, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण आदि की लेनदेन लागत को कम करने के लिए सरकार की ओर से सुविधा की आवश्यकता है। इस पेपर में हमने पिछले दस वर्षों में भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि को देखा है। एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास का केंद्र कहा जाता है। हम भारत में इस क्षेत्र के अवलोकन से शुरुआत करते हैं और कुछ हालिया रुझानों पर नजर डालते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में इस क्षेत्र के विकास और महत्व को उजागर करते हैं। हमने निश्चित निवेश, उत्पादन प्रदर्शन, रोजगार सृजन और निर्यात योगदान में एमएसएमई की वृद्धि का विश्लेषण किया है। विशेष रूप से, हमने रोजगार के अवसरों, बुनियादी ढांचे के विकास, परीक्षण प्रयोगशालाओं, आदि के बारे में चर्चा की है । हमने एमएसएमई की बेहतरी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में दिए गए अवसरों का भी विश्लेषण किया है। निर्यात प्रोत्साहन, आरक्षण नीति, टूलींग और प्रौद्योगिकी, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय कौशल जैसे कारकों ने अर्थव्यवस्था में विकास और बेहतर प्रदर्शन के व्यापक अवसर दिए। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की वृद्धि और विकास के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत ढांचे और कुशल कदमों के योगदान के साथ उल्लेखनीय वृद्धि और उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ms- Subina Sayal (2015) – Role of MSME in India Economy
2. Priyadarshani zanjurme – Growth and Future Prospects of MSME In India
3. Ms- Jyoti Sharma and Ms. Guneet Gill – MSME& An Emerging Piller of Indian Economy

Websites:-

1. www.raijmr.com
2. www.researchgate.net
3. www.caluniv.ac.in